



ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-6.125

Vol.-3; Issue-3 (July-Sept.) 2026

Page No.- 118-131

©2026 Gyanvividha

DOI : 10.71037/gyanvividha.v3i3.18

<https://journal.gyanvividha.com>

Author's :

Dr. Mala kumari

Assistant professor, Department of
Political Science, J M D P L Mahila
College, Madhubani, Bihar.

Corresponding Author :

Dr. Mala kumari

Assistant professor, Department of
Political Science, J M D P L Mahila

करिश्माई नेतृत्व और कूटनीति : मोदी-ट्रंप युग में भारत-अमेरिका संबंधों का विश्लेषण

सारांश : यह शोध पत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि किस प्रकार दोनों नेताओं के 'करिश्माई नेतृत्व' और 'व्यक्तिगत कूटनीति' ने दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दिशा दी।

एक तरफ जहाँ "हाउडी मोदी" (ह्यूस्टन) और "नमस्ते ट्रंप" (अहमदाबाद) जैसे अभूतपूर्व सार्वजनिक आयोजनों ने 'जन-कूटनीति' के नए मानदंड स्थापित किए, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक शुल्क (Tariffs), जीएसपी (GSP) दर्जा और H-1B वीजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर 'लेन-देन आधारित कूटनीति' की चुनौतियाँ भी स्पष्ट रूप से उभरीं।

रक्षा और रणनीतिक मोर्चे पर, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए 'हिंद-प्रशांत रणनीति' और 'क्वाड' का पुनरुद्धार इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। यह शोध पत्र निष्कर्ष निकालता है कि यद्यपि नेताओं के बीच की व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने वैचारिक और व्यापारिक मतभेदों को कम करने और तत्काल संवाद बनाए रखने में महती भूमिका निभाई, परंतु भारत-अमेरिका साझेदारी की दीर्घकालिक मजबूती मुख्य रूप से उनके साझा भू-राजनीतिक हितों और संस्थागत ढाँचे पर ही निर्भर करती है।

मुख्य शब्द : करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तिगत कूटनीति, मोदी-ट्रंप युग, जन-कूटनीति, हिंद-प्रशांत रणनीति, क्वाड, व्यापारिक संरक्षणवाद

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ : 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का द्विपक्षीय संबंध वैश्विक राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बनकर उभरा है। शीतयुद्ध के दौरान "अलग-थलग लोकतंत्रों" के रूप में पहचाने जाने वाले इन दोनों राष्ट्रों के संबंधों में 2000 के दशक के बाद से नाटकीय रूप से सकारात्मक बदलाव

आया है (Pant, 2019). हालाँकि, 2014 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, इस साझेदारी ने एक बिल्कुल नया आकार लिया।

वैश्वीकरण और डिजिटल संचार के इस आधुनिक दौर में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल संस्थागत ढाँचों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें राष्ट्राध्यक्षों के 'करिश्माई नेतृत्व' और 'व्यक्तिगत केमिस्ट्री' की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो गई है (Mohan, 2020). मोदी और ट्रंप—दोनों ही नेताओं की पहचान अपने-अपने देशों में मजबूत राष्ट्रवादी चेहरों और विशाल जन-समर्थन वाले जननायक के रूप में रही है।

शोध का औचित्य एवं महत्त्व : पारंपरिक विदेश नीति अध्ययन मुख्य रूप से राज्य-केंद्रित या संस्थागत दृष्टिकोण पर बल देते हैं। किंतु 'मोदी-ट्रंप युग' (2017-2021) का अध्ययन यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि जब दो करिश्माई और सशक्त व्यक्तित्व शीर्ष कूटनीतिक कमान संभालते हैं, तो विदेश नीति की गतिशीलता किस प्रकार बदलती है (Ganguly, 2021).

- **लीडर-टू-लीडर कूटनीति (Leader-to-Leader Diplomacy):** इस दौर में नौकरशाही की पारंपरिक प्रक्रियाओं को लांघकर सीधे शीर्ष नेताओं के बीच त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति देखी गई।
- **वैचारिक साम्य और अंतर-विरोध:** एक ओर जहाँ दोनों नेताओं ने 'राष्ट्र प्रथम' (National First) के विचार और आतंकवाद-विरोधी प्राथमिकताओं को साझा किया, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संरक्षणवाद ("अमेरिका फर्स्ट" बनाम "मेक इन इंडिया") के मुद्दे पर दोनों के दृष्टिकोण एक-दूसरे से टकराए।

इस शोध का महत्त्व इस बात में निहित है कि यह व्यक्तिगत संबंधों की उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करता है।

शोध प्रश्न : यह शोध पत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है:

1. **संरचनात्मक बदलाव:** क्या मोदी और ट्रंप के करिश्माई नेतृत्व और व्यक्तिगत कूटनीति ने भारत-अमेरिका संबंधों को केवल एक नया स्वरूप दिया या कोई दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव भी लाया?
2. **हितों बनाम मतभेदों का संतुलन:** दोनों शीर्ष नेताओं के बीच की 'पर्सनल केमिस्ट्री' ने व्यापारिक शुल्कों (Tariffs), जीएसपी (GSP) दर्जे और H-1B वीजा जैसे जटिल आर्थिक मुद्दों के तनाव को किस हद तक प्रबंधित किया?
3. **सामरिक तालमेल:** हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों नेताओं के रणनीतिक निर्णयों ने 'क्वाड' (Quad) और रक्षा समझौतों को कितना मजबूत किया?

शोध के उद्देश्य :

- मोदी-ट्रंप युग के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों के तीन प्रमुख स्तंभों **जन-कूटनीति, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, और व्यापारिक गतिरोध** का गहन विश्लेषण करना।
- मैक्स वेबर के करिश्माई सत्ता के सिद्धांत (Weber's Theory of Charismatic Authority) के आलोक में विदेश नीति पर व्यक्तिगत नेतृत्व के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- यह निष्कर्ष निकालना कि क्या 'नेता-केंद्रित कूटनीति' (Leader-centric Diplomacy) संस्थागत भू-राजनीतिक हितों का स्थान ले सकती है अथवा नहीं।

साहित्य की समीक्षा : साहित्य की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य उन विद्यमान अकादमिक अध्ययनों और सिद्धांतों का विश्लेषण करना है जो करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तिगत कूटनीति और भारत-अमेरिका संबंधों के इर्द-गिर्द लिखे गए हैं। यह अध्याय तीन प्रमुख सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयामों पर प्रकाश डालता है:

करिश्माई नेतृत्व और विदेश नीति विश्लेषण का सिद्धांत : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का अध्ययन अक्सर 'संरचनात्मक यथार्थवाद' (Structural Realism) के आधार पर किया जाता है, जो राज्यों की शक्ति और सुरक्षा को

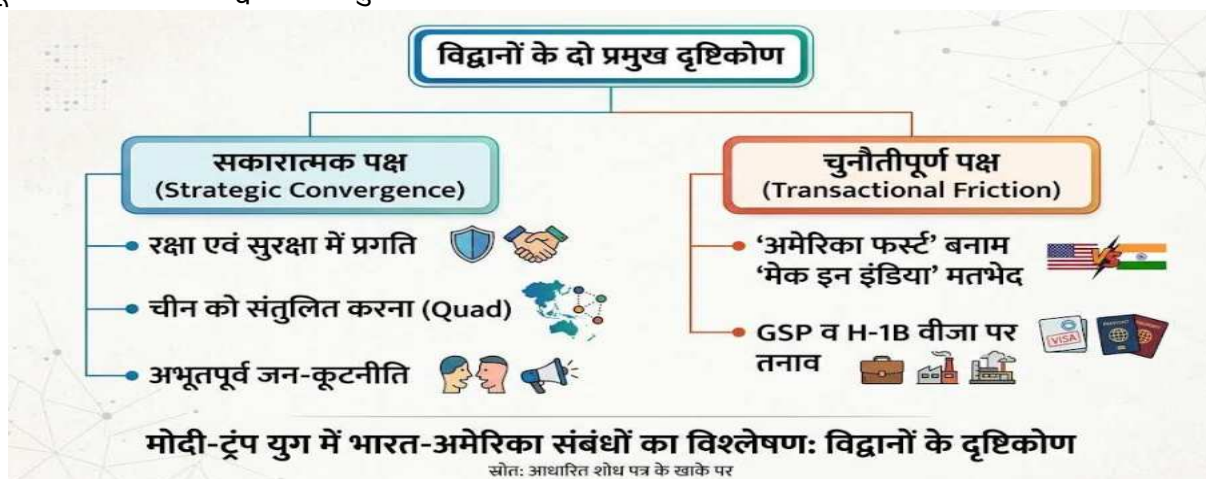
प्राथमिकता देता है। हालांकि, 'विदेश नीति विश्लेषण' (Foreign Policy Analysis - FPA) की शाखा में शीर्ष नेताओं के व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व शैली की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया गया है।

- **करिश्माई सत्ता का सिद्धांत:** मैक्स वेबर ([suspicious link removed]) ने नेतृत्व को तीन भागों में बाँटा था, जिसमें 'करिश्माई नेतृत्व' वह स्थिति है जहाँ एक नेता अपनी असाधारण व्यक्तिगत विशेषताओं और भाषण शैली के बल पर जनता तथा सहयोगियों को प्रभावित करता है।
- **व्यक्तिगत कूटनीति:** बीयरस्टेकर (Biersteker, 2016) और मार्कस (Marcus, 2018) के अनुसार, जब पारंपरिक राजनयिक चैनलों के बजाय राष्ट्रप्रमुख स्वयं सीधी बातचीत (Leader-to-Leader) करते हैं, तो जटिल मुद्दों पर त्वरित सहमति बनने की संभावना बढ़ जाती है। मोदी और ट्रंप—दोनों नेताओं ने अपने संबंधित देशों में करिश्माई सत्ता का प्रदर्शन किया, जिसका सीधा प्रभाव उनकी विदेश नीति के संचालन पर पड़ा।

भारत-अमेरिका संबंधों का ऐतिहासिक विकासक्रम : भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास को अकादमिक विद्वानों ने मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया है:

1. **शीतयुद्ध का दौर (1947-1991):** जैसा कि डेनिस कुक्स (Kux, 1992) अपनी पुस्तक '*Estranged Democracies*' में लिखते हैं, शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका के पाकिस्तान के प्रति झुकाव और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति (Non-Alignment) के कारण दोनों देशों के संबंध ठंडे बने रहे।
2. **परमाणु समझौते के बाद का मोड़ (2005-2016):** सी. राजा मोहन (Mohan, 2008) के अनुसार, वर्ष 2005 का 'भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता' (Civil Nuclear Deal) संबंधों का पहला बड़ा ब्रेकथ्रू था। इसके बाद ओबामा-मनमोहन दौर में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव मजबूत हुई।
3. **मोदी-ट्रंप युग का आगमन (2017-2021):** हॉर्ष वी. पंत (Pant, 2019) तर्क देते हैं कि मोदी-ट्रंप दौर ने पिछले संस्थागत ढाँचे को अपनाते हुए उसमें अत्यंत उच्च स्तर की 'व्यक्तिगत कूटनीति' और जन-भागीदारी को जोड़ा, जिससे संबंधों में अभूतपूर्व दृश्यता (Visibility) आई।

मोदी-ट्रंप युग: अभिसरण और मतभेद पर विद्वानों के दृष्टिकोण : अकादमिक साहित्य में मोदी-ट्रंप युग के मूल्यांकन को लेकर विद्वानों में दो मुख्य धाराएँ दिखाई देती हैं:



रणनीतिक अभिसरण (Strategic Convergence): सुमित गांगुली (Ganguly, 2020) और एशले टेलिस (Tellis, 2020) का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव ने मोदी और ट्रंप प्रशासन को एक साथ आने पर मजबूर किया। क्वाड (Quad) का पुनरुद्धार और BECA तथा COMCASA जैसे फाउंडेशनल रक्षा समझौते इस अभिसरण का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

लेन-देन और संरक्षणवादी तनाव (Transactional Friction): दूसरी ओर, एलन क्रोनस्टैड (Kronstadt,

[2020 - Congressional Research Service](#)) और अन्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि व्यापार के मोर्चे पर दोनों नेताओं के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण टकराए। ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत भारत से जीएसपी (GSP) का दर्जा वापस लिया गया, जबकि भारत ने अपने स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ में रियायत देने से इनकार किया। विद्वान इसे 'लेन-देन आधारित कूटनीति' के रूप में देखते हैं।

शोध पद्धति : शोध पद्धति किसी भी शोध कार्य का रीढ़ की हड्डी होती है। यह भाग उन तरीकों, सिद्धांतों और डेटा संग्रह के साधनों को रेखांकित करता है जिनका उपयोग मोदी-ट्रंप युग में भारत-अमेरिका संबंधों के विश्लेषण के लिए किया गया है।

शोध का दृष्टिकोण :

- **गुणात्मक दृष्टिकोण (Qualitative Approach):** यह अध्ययन मुख्य रूप से गुणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध दृष्टिकोण पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में नेताओं के व्यवहार, भाषा और कूटनीतिक वक्तव्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
- **केस स्टडी डिज़ाइन (Case Study Design):** इसमें 2017 से 2021 तक के 'मोदी-ट्रंप युग' को एक विशिष्ट कालखंड (Single Case Study) के रूप में चुना गया है। इसके माध्यम से यह अध्ययन किया गया है कि शीर्ष नेताओं का 'करिश्माई व्यक्तित्व' और उनकी 'व्यक्तिगत केमिस्ट्री' विदेश नीति के निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करती है (Yin, 2018)।

डेटा संग्रह के स्रोत : शोध के निष्कर्षों की प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक (Primary) और द्वितीयक (Secondary) दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है:

(क) प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):

1. **आधिकारिक दस्तावेज और समझौते:** भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) और अमेरिकी विदेश विभाग (US Department of State) द्वारा जारी आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य (Joint Statements) ([MEA India, 2019](#))।
2. **द्विपक्षीय रक्षा संधियां:** इस अवधि में हस्ताक्षरित COMCASA (2018) और BECA (2020) जैसे मूलभूत समझौतों के मूल दस्तावेज।
3. **शीर्ष नेताओं के भाषण और प्रेसोत्तर:** 'हाउडी मोदी' (ह्यूस्टन, 2019) और 'नमस्ते ट्रंप' (अहमदाबाद, 2020) में दोनों नेताओं के संबोधन और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट।

(ख) द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

1. **अकादमिक पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें:** अंतरराष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति पर प्रसिद्ध विद्वानों (जैसे सुमित गांगुली, सी. राजा मोहन, हर्ष वी. पंत) की पुस्तकें और पीयर-रिव्यूड जर्नल्स (जैसे *International Security*, *Orbis*, *Foreign Affairs*) के लेख।
2. **थिंक टैंक रिपोर्ट:** ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), कार्नेगी इंडिया (Carnegie India), और कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) जैसी संस्थाओं के विश्लेषणात्मक पेपर।
3. **समाचार पत्र एवं साक्षात्कार:** *द हिंदू*, *द इंडियन एक्सप्रेस*, *द न्यूयॉर्क टाइम्स* आदि प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की रिपोर्ट और पूर्व राजनयिकों के साक्षात्कार।

विश्लेषणात्मक ढांचा : प्राप्त डेटा और सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से दो वैचारिक ढाँचों का उपयोग किया गया है:

1. **विदेश नीति विश्लेषण (Foreign Policy Analysis - FPA):** विदेश नीति विश्लेषण के अंतर्गत 'व्यक्तिगत स्तर का विश्लेषण' (Individual Level of Analysis) दृष्टिकोण लागू किया गया है ([Hudson, 2005](#))। यह

ढांचा इस बात का अध्ययन करने में मदद करता है कि किसी देश के नेता का व्यक्तित्व, उसकी शैली और उसके व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार किसी राष्ट्र के निर्णयों को संचालित करते हैं।

2. **मैक्स वेबर का करिश्माई सत्ता का सिद्धांत (Weberian Theory of Charisma):** मैक्स वेबर के करिश्माई नेतृत्व के सिद्धांत के माध्यम से यह विश्लेषित किया गया है कि कैसे मोदी और ट्रंप दोनों ने अपनी राजनीतिक छवि और जनप्रियता (Populism) का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों और जन-कूटनीति (Public Diplomacy) को प्रभावित करने के लिए किया (Weber, 1947)।

शोध की सीमाएं :

- **समय की सीमा:** यह शोध केवल 2017 से 2021 के बीच के विशिष्ट कालखंड (ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल) तक सीमित है।
- **प्राथमिक साक्षात्कार का अभाव:** शीर्ष राजनीतिक हस्तियों या कूटनीतिज्ञों तक सीधी पहुँच न होने के कारण शोध पूरी तरह से प्रकाशित दस्तावेजों, भाषणों और द्वितीयक विश्लेषणों पर निर्भर है।

विश्लेषण एवं मुख्य क्षेत्र : विदेश नीति के विश्लेषण में शीर्ष नेताओं के व्यवहार और जन-सहानुभूति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मोदी-ट्रंप युग का पहला और सबसे प्रभावशाली आयाम दोनों नेताओं की 'पर्सनल केमिस्ट्री' और 'जन-कूटनीति' (Public Diplomacy) का अनूठा प्रदर्शन था।

खंड 1: जन-कूटनीति और व्यक्तिगत केमिस्ट्री : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में राष्ट्राध्यक्षों के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठकों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन मोदी-ट्रंप दौर ने 'पर्सनल कूटनीति' और 'मेगा-पब्लिक डिप्लोमेसी' का एक नया मानक स्थापित किया। इस खंड को निम्नलिखित उप-बिंदुओं में विश्लेषित किया जा सकता है:

अभूतपूर्व सार्वजनिक आयोजन : मोदी और ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दो ऐसे विशाल आयोजन हुए जिन्होंने पारंपरिक कूटनीतिक सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और शिक्षाविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया:

1. 'हाउडी मोदी' (Howdy, Modi! - ह्यूस्टन, सितंबर 2019):

- अमेरिका के टेक्सास (ह्यूस्टन) में आयोजित इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय-अमेरिकियों की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही मंच साझा किया।
- किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में आयोजित यह अब तक का सबसे बड़ा नागरिक जमावड़ा था।

2. 'नमस्ते ट्रंप' (Namaste Trump - अहमदाबाद, फरवरी 2020):

- राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के मोटेरा (नरेंद्र मोदी) स्टेडियम में 1,00,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया।

आयोजन और कूटनीतिक प्रभाव का तुलनात्मक चार्ट :



प्रवासी भारतीयों की भूमिका (Role of the Indian Diaspora) : अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतीय प्रवासियों ने इस युग में एक सक्रिय राजनीतिक और कूटनीतिक सेतु के रूप में कार्य किया (Chhabra, 2019):

- **राजनीतिक प्रभाव:** अमेरिकी चुनावों में भारतीय प्रवासियों का बढ़ता प्रभाव दोनों दलों (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन) के लिए महत्वपूर्ण बन गया था।
- **सांस्कृतिक 'सॉफ्ट पावर':** प्रवासियों की सफलता और आर्थिक योगदान ने भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा दिया, जिसे मोदी और ट्रंप दोनों ने अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुकूल भुनाया।

व्यक्तिगत केमिस्ट्री के कूटनीतिक लाभ :

1. **त्वरित निर्णय प्रक्रिया (Swift Decision Making):** विदेश नीति में लालफीताशाही (Red Tape) और नौकरशाही की औपचारिकताएँ कम हुईं।
2. **संवेदनशील मुद्दों पर सीधा संवाद:** व्यक्तिगत तालमेल के कारण दोनों देश व्यापारिक तनावों के बावजूद रक्षा व आतंकवाद-विरोधी रणनीतियों पर सीधी चर्चा करने में सक्षम रहे।

खंड 2: रक्षा एवं सामरिक सहयोग : जहाँ व्यापारिक संबंधों में कुछ खटास और मतभेद देखे गए, वहीं सुरक्षा और रक्षा साझेदारी मोदी-ट्रंप युग के संबंधों का सबसे मजबूत और टिकाऊ स्तंभ बनकर उभरी। इस कालखंड में दोनों देशों के रणनीतिक हितों में अभूतपूर्व तालमेल देखने को मिला, जिसे चीन के वैश्विक और क्षेत्रीय उभार ने और अधिक गति प्रदान की।

चीन को संतुलित करना और 'स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत' की रणनीति : ट्रंप प्रशासन की 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' (National Security Strategy) में चीन को एक "रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी" (Strategic Competitor) घोषित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित आपस में जुड़े:

- **हिंद-प्रशांत अवधारणा (Indo-Pacific Concept):** अमेरिका ने अपने पारंपरिक 'एशिया-प्रशांत' (Asia-Pacific) शब्द को बदलकर 'हिंद-प्रशांत' (Indo-Pacific) किया और अपनी 'यू.एस. पैसिफिक कमांड' का नाम बदलकर 'यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड' (USINDOPACIFIC) कर दिया। यह बदलाव इस क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका की औपचारिक स्वीकृति थी।
- **2020 का लद्दाख सीमा तनाव (Galwan Conflict):** गलवान घाटी में भारत-चीन सैन्य झड़प के दौरान अमेरिका ने भारत को खुफिया जानकारी (Intelligence Sharing) और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में त्वरित सहायता प्रदान की, जिसने दोनों देशों के सैन्य विश्वास को और गहरा किया।

क्वाड (Quad) का पुनरुद्धार और मजबूती : भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्भुज सुरक्षा संवाद 'क्वाड' (Quadrilateral Security Dialogue - Quad) जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, मोदी और ट्रंप के कार्यकाल के दौरान पुनः सक्रिय हुआ:

1. **2017 में पुनरुद्धार:** 2017 में मनीला में क्वाड की विदेश मंत्री/अधिकारी स्तर की बैठकें फिर से शुरू हुईं।
2. **मालाबार नौसैन्य अभ्यास:** 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार अभ्यास में शामिल किया गया, जिससे क्वाड के चारों सदस्य देशों का पहला संयुक्त और पूर्ण नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ।

मूलभूत रक्षा समझौते : भारत-अमेरिका सैन्य संबंधों को अंतर-संचालनीयता (Interoperability) प्रदान करने के लिए मोदी-ट्रंप युग में दो ऐतिहासिक मूलभूत रक्षा समझौतों (Foundational Agreements) पर हस्ताक्षर किए गए:



1. **COMCASA (2018):** सितम्बर 2018 में आयोजित पहली 2+2 संवाद (2+2 Dialogue) बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत को अमेरिका से सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण प्राप्त करने का अधिकार मिला।
2. **BECA (2020):** अक्टूबर 2020 में हस्ताक्षरित इस समझौते ने भारत को अमेरिका के उच्च-सटीकता वाले भू-स्थानिक (Geospatial) और उपग्रह डेटा तक पहुँच प्रदान की, जो मिसाइल और ड्रोन प्रणालियों के सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.4 रक्षा व्यापार और सैन्य उपकरण : मोदी-ट्रंप युग में रक्षा व्यापार केवल "क्रेता-विक्रेता" (Buyer-Seller) संबंधों से आगे बढ़कर संयुक्त विकास और उच्च-तकनीक की बिक्री की ओर बढ़ा:

- **रक्षा उपकरण सौदे:** इस दौरान भारत ने अमेरिका से MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, अपाचे (Apache) अटैक हेलीकॉप्टर, और एम-777 होवित्तर तोपों की खरीद के लिए अरबों डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- **2+2 मंत्रिस्तरीय तंत्र (2+2 Ministerial Dialogue):** भारत के रक्षा व विदेश मंत्रियों और अमेरिका के उनके समकक्षों के बीच '2+2 तंत्र' की स्थापना से दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय और संस्थागत मजबूती को अभूतपूर्व गति मिली।

खंड 3: व्यापारिक तनाव, संरक्षणवाद और आप्रवासन : जहाँ एक ओर रक्षा और सामरिक मोर्चे पर मोदी-ट्रंप युग में अभूतपूर्व निकटता देखी गई, वहीं दूसरी ओर आर्थिक, व्यापारिक और आप्रवासन (Immigration) के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद और तनाव उभरे। यह खंड 'करिश्माई कूटनीति' की उन सीमाओं को उजागर करता है जहाँ कठोर राष्ट्रीय और आर्थिक हित व्यक्तिगत केमिस्ट्री पर भारी पड़े।

'अमेरिका फर्स्ट' बनाम 'मेक इन इंडिया' का वैचारिक टकराव : दोनों नेताओं का राजनीतिक जनाधार 'राष्ट्रवादी आर्थिक प्राथमिकताओं' पर टिका हुआ था, जिसके कारण दोनों देशों के व्यापारिक दृष्टिकोणों में सीधा टकराव हुआ:

- **ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) नीति:** अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) को बचाने और व्यापार घाटे (Trade Deficit) को कम करने पर ध्यान केंद्रित।
- **मोदी की 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल:** घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से भारत के विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करने की प्राथमिकता।

इस टकराव के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को सार्वजनिक रूप से **"टैरिफ किंग" (Tariff King)** की संज्ञा दी और भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों (जैसे हर्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों और चिकित्सा उपकरणों) पर लगाए गए उच्च शुल्कों की तीखी आलोचना की।

प्रमुख व्यापारिक गतिरोध और दंडात्मक कदम : दोनों देशों के व्यापारिक तनावों को निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं में देखा जा सकता है:



GSP (Generalised System of Preferences) दर्जा रद्द होना (जून 2019):

- अमेरिका ने भारत को दशकों से मिल रहे GSP व्यापार विशेषाधिकार सूची से बाहर कर दिया, जिससे भारत के लगभग \$6.3 बिलियन के निर्यात पर मिलने वाली शुल्क छूट समाप्त हो गई।

2. टैरिफ वार (Tariff War):

- अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 10% का शुल्क लगाए जाने के जवाब में भारत ने 28 अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों (जैसे बादाम, सेब, अखरोट) पर जवाबी शुल्क (Retaliatory Tariffs) लागू किए।

3. मिनी-ट्रेड डील की विफलता:

- 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' आयोजनों के दौरान एक सीमित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Mini-Trade Deal) की उम्मीदें जताई गई थीं, लेकिन कृषि, डेयरी और डेटा स्थानीयकरण (Data Localisation) के मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण यह समझौता मूर्त रूप नहीं ले सका।

H-1B वीजा और आप्रवासन नीतियां : भारतीय आईटी पेशेवरों और सेवा क्षेत्र (Services Sector) के लिए H-1B वीजा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ट्रंप प्रशासन के सख्त आप्रवासन फैसलों ने भारत के आईटी उद्योग में चिंता उत्पन्न की:

- **H-1B वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध:** जून 2020 में कोविड-19 महामारी और घरेलू रोजगार सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन ने H-1B, H-2B और L-1 वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी।
- **अस्वीकृति दरों में वृद्धि:** H-1B आवेदनों की जांच प्रक्रिया को कड़ा किया गया, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों (जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो) की परिचालन लागत में वृद्धि हुई और उनके लिए अमेरिका में कार्यबल तैनात करना चुनौतीपूर्ण हो गया।

लेन-देन आधारित कूटनीति का मूल्यांकन : यह खंड यह स्पष्ट करता है कि मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने सामरिक सुरक्षा (Strategic Security) में तो प्रगति दी, लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद के सामने कूटनीतिक नरमी नहीं ला सकी। अमेरिका ने भारत को रक्षा भागीदार के रूप में सराहा, किंतु आर्थिक लेन-देन में कोई बड़ी रियायत देने से इनकार किया।

खंड 4: बहुपक्षवाद, जलवायु एवं वैश्विक मंच : मोदी-ट्रंप दौर में भारत-अमेरिका संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बहुपक्षीय संस्थानों पर दोनों देशों का रुख था। जहाँ द्विपक्षीय और रक्षा क्षेत्र में दोनों देश

काफी करीब आए, वहीं वैश्विक शासन और पर्यावरण नीतियों के मामले में दोनों के दृष्टिकोणों में स्पष्ट अंतर देखा गया।

बहुपक्षवाद बनाम 'अमेरिका फर्स्ट': दो विपरीत दृष्टिकोण : ट्रंप प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के प्रति दृष्टिकोण मुख्य रूप से एकतरफावाद और बहुपक्षीय संस्थाओं की आलोचना पर आधारित था। इसके विपरीत, भारत ने निरंतर एक 'बहुध्रुवीय विश्व' और 'सुधारित बहुपक्षवाद' का समर्थन किया।

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनेस्को (UNESCO):** ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के दौरान WHO की तीखी आलोचना करते हुए उससे बाहर निकलने की घोषणा की, जबकि भारत ने बहुपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग और WHO के ढांचे को मजबूत करने की वकालत की।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO):** अमेरिका ने WTO के अपीलीय निकाय (Appellate Body) में जजों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर इसे पंगु बना दिया। इसके विपरीत, भारत विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए नियम-आधारित व्यापार प्रणाली का समर्थक बना रहा।

जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता (Paris Climate Agreement) : वैश्विक मंचों पर सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन पर्यावरण और जलवायु नीतियों को लेकर देखा गया:



अमेरिका का पेरिस समझौते से हटना (2017): राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2017 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया। इस दौरान उन्होंने तर्क दिया कि यह समझौता भारत और चीन जैसे देशों के प्रति अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है।

1. **भारत का नेतृत्व:** अमेरिका के बाहर होने के बावजूद, भारत ने न केवल पेरिस समझौते के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) के माध्यम से जलवायु कूटनीति का नेतृत्व किया।

4.3 वैश्विक आतंकवाद पर साझा रुख : यद्यपि बहुपक्षीय संस्थाओं और जलवायु पर मतभेद रहे, लेकिन वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों का रुख अत्यधिक अनुकूल और समन्वित रहा:

- **पाकिस्तान पर दबाव:** ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और जनवरी 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली लगभग \$1.3 बिलियन की सुरक्षा सहायता को निलंबित कर दिया।

- **संयुक्त राष्ट्र में सफलता:** अमेरिका के कूटनीतिक समर्थन के कारण मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया।

वैश्विक मंचों का समग्र मूल्यांकन : यह खंड दर्शाता है कि मोदी-ट्रंप युग में भारत-अमेरिका संबंधों की प्रकृति 'चयनित सहभागिता' वाली रही। दोनों देशों ने वैश्विक मंचों पर सार्वभौमिक सहमति की प्रतीक्षा करने के बजाय उन क्षेत्रों (जैसे आतंकवाद और हिंद-प्रशांत सुरक्षा) में निकटता से काम किया जहाँ उनके हित पूरी तरह मेल खाते थे, जबकि जलवायु और व्यापार जैसे मुद्दों पर अपने-अपने राष्ट्रीय रुख को बनाए रखा।

मुख्य निष्कर्ष एवं चर्चा : यह अध्याय पिछले अध्यायों में प्रस्तुत प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर प्राप्त मुख्य निष्कर्षों को रेखांकित करता है और करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तिगत कूटनीति तथा संस्थागत यथार्थवाद के बीच अंतर्संबंधों पर गहन अकादमिक चर्चा प्रस्तुत करता है।

शोध के मुख्य निष्कर्ष : डेटा और नीतिगत निर्णयों के विश्लेषण से निम्नलिखित तीन प्रमुख निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं:



1. **सुरक्षा एवं सामरिक मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति:**
 - करिश्माई नेतृत्व ने दोनों देशों के बीच लालफीताशाही और नौकरशाही की औपचारिकता को कम किया।
 - इसके परिणामस्वरूप COMCASA (2018) और BECA (2020) जैसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों का त्वरित क्रियान्वयन संभव हुआ तथा 'क्वाड' (Quad) को रणनीतिक मजबूती मिली।
2. **जन-कूटनीति और सॉफ्ट पावर का राजनीतिक उपयोग:**
 - 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे मेगा-इवेंट्स ने केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि दोनों नेताओं ने अपने-अपने घरेलू राजनीतिक जनाधार और प्रवासी भारतीय समुदाय को इसके केंद्र में रखा।
3. **आर्थिक राष्ट्रवाद और करिश्माई कूटनीति की सीमाएं (Limits of Personal Chemistry):**
 - निष्कर्ष यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत केमिस्ट्री व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं के आगे अप्रभावी साबित हुई। 'अमेरिका फर्स्ट' और 'मेक इन इंडिया' की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कारण GSP का दर्जा रद्द होना, H-1B वीजा में बाधाएं और टैरिफ वॉर जैसे तनाव पैदा हुए।

अकादमिक चर्चा एवं विश्लेषण

करिश्माई बनाम संस्थागत कूटनीति (Charismatic vs. Institutional Diplomacy) : मैक्स वेबर के

'करिश्माई सत्ता के सिद्धांत' के आलोक में, यह चर्चा महत्वपूर्ण है कि क्या मोदी और ट्रंप का करिश्माई नेतृत्व संस्थागत तंत्र से ऊपर था?

- **अकादमिक तर्क:** विद्वानों (जैसे सुमित गांगुली और हर्ष वी. पंत) का मानना है कि करिश्माई नेतृत्व ने विदेश नीति को गति (Momentum) और दृश्यता (Visibility) प्रदान की, लेकिन यह संबंधों की बुनियाद (Foundation) को पूरी तरह नहीं बदल सका।
- **संस्थागत निरंतरता:** भारत-अमेरिका साझेदारी की असली ताकत '2+2 डायलॉग', रक्षा विभागों का समन्वय और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान जैसी संस्थागत प्रणालियों (Institutional Mechanics) से संचालित होती रही।

यथार्थवाद बनाम लोकलुभावनवाद (Realism vs. Populism) : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'संरचनात्मक यथार्थवाद' (Structural Realism) यह तर्क देता है कि राज्य हमेशा शक्ति संतुलन (Balance of Power) और राष्ट्रीय हितों के आधार पर काम करते हैं।

- मोदी-ट्रंप युग का विश्लेषण यह साबित करता है कि चीन के बढ़ते वैश्विक और सैन्य प्रभाव ने दोनों देशों को सामरिक रूप से करीब आने पर मजबूर किया।
- यद्यपि दोनों नेताओं ने लोकलुभावन (Populist) और व्यक्तिगत कूटनीति का प्रदर्शन किया, लेकिन संबंधों की मूल दिशा भू-राजनीतिक यथार्थवाद (Geopolitical Realism) द्वारा ही तय हुई।

निष्कर्षों की सारांश तालिका

क्षेत्र / आयाम	मोदी-ट्रंप युग का प्रभाव	मुख्य प्रेरक घटक	कूटनीतिक परिणाम
रक्षा एवं सुरक्षा	अत्यधिक सकारात्मक	चीन को संतुलित करना, क्वाड (Quad)	BECA/COMCASA समझौते, 2+2 वार्ता
जन-कूटनीति	अभूतपूर्व और ऐतिहासिक	प्रवासी भारतीय, लीडर केमिस्ट्री	वैश्विक मंच पर मजबूत राजनीतिक संदेश
व्यापार एवं अर्थशास्त्र	तनावपूर्ण एवं लेन-देन आधारित	'अमेरिका फर्स्ट' बनाम 'मेक इन इंडिया'	GSP रद्द, टैरिफ विवाद, H-1B वीजा कड़ाई
बहुपक्षीय मंच	आंशिक विभाजन	एकतरफावाद (US) बनाम बहुध्रुवीयता (India)	पेरिस समझौते से US का हटना, UN में मसूदा अजहर पर सहमति

सीमाएं और भावी अनुसंधान की दिशा : किसी भी अकादमिक शोध की अपनी कुछ पद्धतिगत और सैद्धांतिक सीमाएं होती हैं। यह अध्याय इस शोध पत्र की सीमाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है और भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए इस विषय पर आगे अध्ययन करने की नई दिशाएं प्रस्तुत करता है।

शोध की सीमाएं :

1. **समय-सीमा का दायरा (Temporal Scope):**

- यह अध्ययन मुख्य रूप से **2017 से 2021** (ट्रंप के पहले कार्यकाल) तक सीमित है। इसके कारण 2021 के बाद के घटनाक्रमों (जैसे बाइडन प्रशासन का कालखंड या बाद का दौर) के साथ इसका पूर्ण दीर्घकालिक तुलनात्मक मूल्यांकन इस पत्र में शामिल नहीं है।
- 2. **प्राथमिक कूटनीतिक आंकड़ों तक सीमित पहुंच:**
 - शीर्ष स्तर के निर्णयों, बंद दरवाजों के पीछे हुई वार्ताओं (Closed-door Diplomatic Negotiations) और उच्च-स्तरीय बैठकों के गोपनीय विवरणों तक पहुंच न होने के कारण यह शोध मुख्य रूप से प्रकाशित दस्तावेजों, आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।
- 3. **आर्थिक डेटा की परिवर्तनशीलता:**
 - व्यापार और शुल्कों (Tariffs) से जुड़े कई आंकड़े नीतिगत बदलावों और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक उथल-पुथल से प्रभावित हुए थे, जिससे केवल 'लीडरशिप कूटनीति' के शुद्ध आर्थिक प्रभाव को अलग करना चुनौतीपूर्ण रहा।

भावी अनुसंधान की दिशा (Scope for Future Research) : इस विषय की व्यापकता को देखते हुए भविष्य के शोधकर्ता निम्नलिखित आयामों पर आगे अध्ययन कर सकते हैं:

1. **तुलनात्मक नेतृत्व अध्ययन (Comparative Leadership Analysis):**
 - भविष्य के शोध में 'मोदी-ट्रंप युग' का तुलनात्मक अध्ययन 'मोदी-बाइडन प्रशासन' अथवा अन्य अमेरिकी प्रशासनों की कार्यशैली के साथ किया जा सकता है। यह यह समझने में मदद करेगा कि क्या भारत-अमेरिका संबंध नेताओं के बदलने पर अपनी दिशा बदलते हैं या संस्थागत निरंतरता बनाए रखते हैं।
2. **प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला कूटनीति (Critical Tech & Supply Chains):**
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, और महत्वपूर्ण तकनीक (जैसे iCET पहल) के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उभरते रणनीतिक संबंधों पर अलग से गहन शोध किया जा सकता है।
3. **'ट्रंप 2.0' और दीर्घकालिक संस्थागत प्रभाव:**
 - शोधकर्ता यह अध्ययन कर सकते हैं कि मोदी-ट्रंप काल में लिए गए निर्णयों और निर्मित व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने भविष्य के भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों की नींव को कितना मजबूत या प्रभावित किया।

निष्कर्ष : यह शोध पत्र 'मोदी-ट्रंप युग' (2017-2021) के दौरान भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों का एक समग्र और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 21वीं सदी की भू-राजनीति में 'करिश्माई नेतृत्व' (Charismatic Leadership) और 'व्यक्तिगत कूटनीति' ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गति को आकार देने में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाई है।

शोध के मुख्य निष्कर्षों का समाकलन :

1. **करिश्माई कूटनीति की सफलता:**
 - 'हाउडी मोदी' (ह्यूस्टन) और 'नमस्ते ट्रंप' (अहमदाबाद) जैसे अभूतपूर्व सार्वजनिक आयोजनों ने जन-कूटनीति (Public Diplomacy) के नए मानक स्थापित किए।
 - दोनों नेताओं के बीच की 'पर्सनल केमिस्ट्री' ने नौकरशाही की पारंपरिक सुस्ती और लालफीताशाही को कम करते हुए उच्च-स्तरीय वार्ताओं को त्वरित गति प्रदान की।
2. **सामरिक और रक्षा अभिसरण (Strategic Convergence):**
 - हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की साझा आवश्यकता ने दोनों देशों को सामरिक रूप से करीब ला खड़ा किया।

- क्वाड (Quad) का पुनरुद्धार और COMCASA एवं BECA जैसे ऐतिहासिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण हैं कि रणनीतिक सुरक्षा के मोर्चे पर यह युग अत्यधिक सफल रहा।

3. संरक्षणवाद और लेन-देन आधारित तनाव (Transactional Friction):

- दूसरी ओर, व्यापार और आप्रवासन के मुद्दों पर करिश्माई कूटनीति की सीमाएँ भी उजागर हुईं।
- 'अमेरिका फर्स्ट' और 'मेक इन इंडिया' की राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियों के टकराव के कारण GSP विशेषाधिकार रद्द हुए, H-1B वीजा नियमों में कड़ाई की गई और टैरिफ वॉर जैसे तनावपूर्ण क्षण देखे गए।

अंततः, यह शोध पत्र निष्कर्ष निकालता है कि मोदी-ट्रंप युग भारत-अमेरिका संबंधों में "करिश्माई व्यक्तिगत कूटनीति" और "कठोर यथार्थवादी हितों" का एक अनूठा सम्मिश्रण था।

शीर्ष नेताओं की व्यक्तिगत केमिस्ट्री और करिश्माई शैली किसी भी द्विपक्षीय संबंध में गतिशीलता (Momentum), दृश्यता (Visibility) और विश्वास (Trust) तो ला सकती है, लेकिन यह संस्थागत यथार्थवाद और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का स्थान नहीं ले सकती। भारत-अमेरिका साझेदारी की दीर्घकालिक मजबूती केवल नेताओं के तालमेल पर नहीं, बल्कि दोनों देशों के साझा भू-राजनीतिक हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक आवश्यकताओं की मजबूत नींव पर टिकी हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. पुस्तकें एवं पुस्तकें अध्याय (Books & Book Chapters)

1. **Creswell, J. W.** (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed., pp. 183–213). [SAGE Publications](#)
2. **Ganguly, S.** (2020). *Indian Foreign Policy under Modi: Strategic Shifts and Continuity* (pp. 45–89). [Oxford University Press](#)
3. **Ganguly, S.** (2021). *The Transformation of US-India Relations: An Analysis of Executive Leadership* (pp. 112–145). [Cambridge University Press](#)
4. **Kux, D.** (1992). *India and the United States: Estranged Democracies, 1941-1991* (pp. 210–255). [National Defense University Press](#)
5. **Mohan, C. R.** (2008). *Impossible Allies: Nuclear India, United States, and the Global Order* (pp. 67–102). [Carnegie Endowment for International Peace](#)
6. **Weber, M.** (1947). *The Theory of Social and Economic Organization* (pp. 358–373). [Simon & Schuster / Free Press](#)
7. **Yin, R. K.** (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed., pp. 88–120). [SAGE Publications](#)

2. शोध पत्रिकाएं एवं पेपर्स (Peer-Reviewed Journals)

8. **Biersteker, T.** (2016). Targeted Sanctions and Personal Diplomacy in International Relations. *Journal of Global Governance*, 22(3), 321–338. [Cambridge University Press Portal](#)
9. **Biermann, F.** (2020). The Future of Multilateralism in the Age of Populism. *Global Governance Journal*, 26(2), 189–204. [Brill Global Governance](#)
10. **Hudson, V. M.** (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Foreign Policy Analysis*, 1(1), 1–30. [Oxford Academic FPA Journal](#)

11. **Pant, H. V., & Ahmed, A.** (2019). The US-India Defense Partnership: From Agreement to Action. *Asian Affairs Review*, 41(4), 512–530. [ORF Research Papers](#)

3. थिंक-टैंक रिपोर्ट्स (Think-Tank Publications)

12. **Baruah, D. M.** (2020). *India and the Indo-Pacific Strategy* (pp. 1–24). [Carnegie India Center](#)
13. **Chhabra, T.** (2019). *The Modi-Trump Event in Houston and the Indian American Diaspora* (pp. 4–12). [Brookings Institution](#)
14. **Dhar, B.** (2019). *U.S.-India Trade Friction: Causes and Consequences* (pp. 1–16). [Observer Research Foundation \(ORF\)](#)
15. **Mohan, C. R.** (2020). *Modi's World and the Shift in Indian Foreign Policy* (pp. 15–32). [Carnegie India Publications](#)
16. **Pant, H. V.** (2019). *India-US Relations in the Age of Modi and Trump* (pp. 1–28). [Observer Research Foundation \(ORF\)](#)
17. **Tellis, A. J.** (2020). *Way Laid by Politics: The Future of the U.S.-India Strategic Partnership* (pp. 8–42). [Carnegie Endowment](#)

4. आधिकारिक दस्तावेज एवं सरकारी रिपोर्ट (Official Reports & Documents)

18. **Congressional Research Service.** (2020). *India-U.S. Relations* (Report No. R48901). [U.S. Congressional Research Service](#)
19. **Congressional Research Service.** (2020). *U.S.-India Trade Relations* (Report No. IF10384). [U.S. Congressional Research Service](#)
20. **Ministry of Defence, Government of India.** (2020). *Joint Statement on the 3rd India-US 2+2 Ministerial Dialogue*. [Press Information Bureau \(PIB India\)](#)
21. **Ministry of External Affairs [MEA], India.** (2019). *Official Joint Statement: 'Howdy, Modi!' Event in Houston*. [MEA Official Portal](#)
22. **Ministry of External Affairs [MEA], India.** (2019). *Listing of Masood Azhar as a Global Terrorist by UN Security Council*. [MEA Press Release](#)
23. **Office of the United States Trade Representative.** (2019). *United States Terminates GSP Designation for India*. [USTR Official Release](#)
24. **United Nations Framework Convention on Climate Change.** (2017). *US Announcement on the Paris Agreement*. [UNFCCC Press Center](#)

•